ईएसआई मेडिकल कॉलेज के डीन का कड़ा विरोध पत्र

सेवा में,
श्री सतीश कुमार
संम्पादक, मज़दूर मोर्चा,
विषय : निराधार समाचार खंडन बाबत।
महोदय,

'मज़दूर मोर्चा' साप्ताहिक फ़रीदाबाद क्षेत्र के मज़दूरों की सशक्त आवाज के रूप में जाना जाता है। परंतु आपके 2-8 अप्रैल के अंक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदाबाद के सम्बन्ध में कुछ निराधार और काल्पनिक समाचार पढ़ कर निराशा हुई। पत्रकारिता के मूल्यों का तकाज़ा था कि रिपोर्ट छापने से पूर्व संस्थान से जुड़े किसी भी मुद्दे पर डीन या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर सही जानकारी प्राप्त की जाती। खेद है कि आप ऐसा करने से चूक गये और आपकी चूक एक भ्रामक रिपोर्ट का बायस बनी।

अत: उक्त अंक में आपके द्वारा प्रकाशित त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट का मैं अपने संस्थान की ओर से औपचारिक खंडन करता हूं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के एक संस्थान के मुखिया की हैसियत से अपना कर्तव्य समझता हूं कि मामले से सम्बन्धित सही तथ्य आपके पाठकों के समक्ष रखूं ताकि कोई तथ्यात्मक भ्रम की स्थिति न बने।

प्रथमत: यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि डीन डॉ. असीम दास द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यक्गित कारणों से त्यागपत्र दिया था, और उक्त त्यागपत्र का सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत न किया जाना एक विशुद्ध प्रशासनिक निर्णय था, जो कि मेरे द्वारा त्यागपत्र को वापस लेने के फैसले को ध्यान में रख कर लिया गया। उक्त प्रकरण में आपके द्वारा लगाये गये कयास ना सिर्फ दुर्भावना से ग्रसित हैं, बल्कि आपकी रिपोर्ट के उस हिस्से में मानक प्रशासनिक तौर-तरीकों की जानकारी का अभाव भी झलकता है।

यह भी स्पष्ट हो कि माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव का मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रांगण में आगमन भारत के युवा प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण के उद्देश्य से हुआ था तथा इसी क्रम में अस्पताल प्रशासन द्वारा आरंभ की गई कुछ नई सुविधाओं का भी उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया गया। संस्थान के अभिभावक की हैसियत से माननीय मंत्री द्वारा किए गए प्रतिमा अनावरण और उद्घाटन को 'नाटक' करार देना असंसदीय तथा अभद्र टिपण्णी है जिसका मैं पुरजोर खंडन करता हूं।

आपने अपने लेख में दो कमरों का उद्घाटन का ज़िक्र भी जिस अंदाज में किया है वह भी सत्य से परे है, क्योंकि आपको उस दो कमरों का महत्व और मूल्य पता नहीं है।

सूचित हो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के रोगियों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिये निगेटिव प्रेशर एएचयू और हेपा एयर फिल्टर से लैस इन कमरों की सुविधा शुरू हो गई है।

आपकी जानकारी के लिये, सरकारी संस्थानों के एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ के बाद यह इस क्षेत्र का तीसरा सरकारी संस्थान है जहां ये सुविधा उपलब्ध है। पिछले एक साल से ये सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के तहत दी जा रही थी। उस दरम्यान 26 बीएमटी सफलतापूर्वक किया गया जिससे संस्थान के चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी और पैरामेडिकल कर्मियों का भरोसा बढ़ा और ज्यादा मरीजों के उपचार के लिये और सुविधा बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन मिला।

उक्त दो कमरे के अतिरिक्त यूनिट जुड़ने से उत्कृष्ट सेवा का विस्तार किया जायेगा और बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यहां भी आपकी लेखनी दुर्भावना और पक्षपातपूर्ण रही, जो कतई स्वीकार्य नहीं। शायद आपको इसकी बारीकियों का अंदाजा नहीं है या आप दुर्भावना से ग्रसित हैं।

विद्यार्थियों के लिये हॉस्टल की व्यवस्था पर आपकी रिपोर्ट भी निराधार और त्रुटिपूर्ण है। ज्ञात हो कि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि और पीजी कोर्स आरंभ एक साथ हो जाने से विद्यार्थियों के लिये हॉस्टल की फौरी तौर पर कमी है जिसका पर्याप्त समाधान प्रशासन द्वारा कर लिया गया है। इस समस्या के दीर्घावधि समाधान हेतु प्रांगण के भीतर ही हॉस्टल की नई इमारत की योजना अमल में लाई जायेगी।

इसके अतिरिक्त छुट्टी के दिन कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाने सम्बन्धी आपकी भ्रामक और तथ्यहीन रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहना है कि उद्घाटन संस्थान हॉस्पिटल होने की वजह से विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों का छुट्टी के दिन भी कार्यालय में काम-काज करना एक सामान्य परिघटना है। ज्ञात हो कि ऐसी अतिरिक्त ड्यूटी के एवज़ में कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टी या अतिरिक्त वेतन देने का प्रावधान है जिसका पालन अस्पताल प्रशासन पूरी निष्ठा से करता है।

अंत में आपसे इस अनुरोध के साथ अपनी कहन को विराम दूंगा कि पत्रकारिता के सत्यापित मूल्यों का निर्वहन करते हुए 'मज़दूर मोर्चा' साप्ताहिक के अगले अंक में इस खंडन को प्रकाशित करने का श्रम करें।

साथ ही यह भी निवेदन रहेगा कि भविष्य में संस्थान के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट छापने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करने में संकोच ना करें ताकि आपके पाठकों में भ्रम की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो और कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल जैसे मज़दूरों के अपने प्रतिष्ठित संस्थान के सम्मान को ठेस ना पहुंचे।

सादर
डॉ असीम दास
डीन
DEAN
ESIC Medical College & Hospital
NH-3, M.I.T. Faridabad-121001 (Hr.)

हमारा जवाब : मजदूर मोर्चा का नजरिया अलग रहा है

साप्ताहिक 'मज़दूर मोर्चा' को आपने मज़दूरों की सशक्त आवाज समझा इसके लिये आपका धन्यवाद। लेकिन हमारे गतांक यानी 2-8 अप्रैल के अंक में आपके संस्थान को लेकर प्रकाशित समाचार को निराधार एवं दुर्भावनापूर्ण बताये जाने से हम सहमत नहीं हैं। रविवार 26 मार्च को मंत्रियों के आगमन की सूचना और प्रेस नोट न मिलने की वजह से हमने अपने स्तर पर सामग्री जुटाने का प्रयास किया था। आपसे सम्पर्क करके प्रेस नोट हासिल न करने के लिये हमें खेद है।

आपके इस कथन से हम सहमत नहीं हैं कि केन्द्रीय श्रममंत्री द्वारा उद्घाटित दो कमरों के महत्व को हम नहीं समझते। इसके महत्व को हम कितना समझते हैं, उसे हमारे दिनांक 7-13 अगस्त 2022 के अंक से समझा जा सकता है। उसमें हमने 'ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 11 सफल केस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में लिखा था, '.....डॉ. राहुल भार्गव ने बातचीत में बताया कि इलाज की प्रक्रिया के लिये सर्वप्रथम हेपाफिल्टर युक्त आइसोलेशन कमरे की आवश्यकता होती है ताकि कमरे में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कोई कण अथवा बैक्टीरिया आदि प्रवेश न कर सके। इस कमरे में मरीज़ को करीब 25 दिन रखा जाता है। शुरू में एक कमरे में एक ही मरीज़ रखा गया था, बाद में दो रखने लगे।.....डॉ. भार्गव का कहना है कि जिस तरह से यहां मरीज़ पहुंचने लगे हैं उसे देखते हुए यहां पूरा सेंटर ऑफ़ एक्सिलेंस बनाना पड़ेगा जिसके लिये 50-100 कमरों तक की आवश्यकता होगी।'

मज़दूरों की सशक्त आवाज होने के नाते 'मज़दूर मोर्चा' अपेक्षा करता था कि मंत्री महोदय बढ़ती आवश्यकता के अनुरूप कम से कम 50 कमरों के वार्ड का निर्माण कार्य शुरू करायेंगे। निर्माण कार्य तो दूर अभी तक इसके लिये आवश्यक ट्रेंड स्टाफ़ की भर्ती प्रक्रिया तक शुरू नहीं की जा सकी है। मजदूर मोर्चा की टिप्पणी का यही आधार है।

छात्रावास को लेकर, संस्थान मुखिया के नाते डीन साहब का तो कहना बनता है जो वे कह रहे हैं। लेकिन हम उससे सहमत नहीं हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एमबीबीएस की 100 सीटों को बढ़ा कर 150 किया था, उसी दिन उनके आवास के लिये हॉस्टल निर्माण का कार्य क्यों शुरू नहीं कराया? दुख तो इस बात का है कि अभी तक हॉस्टल निर्माण का कोई एजेंडा किसी काग़ज पर नजर नहीं आ रहा। इसके साथ-साथ पीजी छात्रों की बढ़ती संख्या के लिये परिसर में रिहायश न होना गंभीर चिंता का विषय है। फिलहाल जो अस्थायी आवास व्यवस्था की गई है उस पर होने वाला भारी-भरकम खर्चा व समय की बर्बादी भी कम चिंतनीय नहीं है।

डीन साहब के इस्तीफे वाली नोटिस को लेकर, हो सकता है कि हमें कोई भ्रम रहा हो। फिर भी हम अपने 11-17 सितम्बर 2022 के अंक में 'डीन ने दिया इस्तीफे का नोटिस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे। इसमें, संस्थान में बढ़ते कार्यभार व स्टाफ़ की भारी कमी के कारण चिंतित व आए दिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हमने डीन डॉक्टर असीम दास को देखा है। इसी के चलते उन्हें बीपी व शुगर जैसी बीमारियों से दो-चार होते भी देखा है। इसके बावजूद भी हम डीन का पक्ष ज्यों का त्यों दे रहे हैं।

इसी के संदर्भ में 5-11 फरवरी 2023 के अंक में 'ईएसआई मेडिकल कॉलेज पांव जंजीर से बंधे हैं फिर भी ऊंची उड़ान जारी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार भी देखा जाना चाहिये। इसमें कहा गया है कि मुख्यालय की ओर से खड़ी की जाने वाली तमाम बाधाओं के बावजूद संस्थान लगातार नये-नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसके चलते ग़रीब मज़दूरों को अकल्पनीय चिकित्सा लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी तमाम मज़दूर दिल की गहराइयों से प्रशंसा करते हैं।

कोई भी अस्पताल 24X7 सेवा देने के लिये बना होता है। इसे चलाने के लिये ड्यूटी रोस्टर बने होते हैं। इसके बावजूद संकटकालीन स्थिति में सारे स्टाफ़ को भी एक साथ बुलाया जा सकता है। लेकिन मंत्रियों के भाषण व उनके साथ बैठकर पीएम मोदी के मन की बात सुनने के लिये नहीं। अच्छी बात है कि आप उस दिन के लिये कर्मचारियों को छुट्टी अथवा वेतन दे रहे हैं। इस बात का ज्ञान उन कर्मचारियों को नहीं था जिन्होंने अपना पक्ष **'मज़दूर मोर्चा'** के सामने व्यक्त किया था।

नि:संदेह विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, लेकिन उनसे प्रेरणा पाने के लिये किसी को भी मध्यस्थ के रूप में मंत्रियों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये; विशेष कर उन मंत्रियों की तो कतई नहीं जिन्होंने खुद किसी प्रेरणा के लायक जन कार्य न करें हों।

विश्व में मेडिकल सिक्योरिटी में ईएसआईसी से बेहतर कोई स्कीम नहीं है: केन्द्रीय श्रम मंत्री

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

मूर्ति अनावरण के लिए पधारे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में अपने लच्छेदार भाषण के दौरान केन्द्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र सिंह यादव ने उक्त हकीकत बयान करते हुए अपने साथ खड़े ईएसआई कार्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल राजेन्द्र कुमार की ओर देखते हुए कुछ बेहतर काम करने का इशारा किया। लेकिन अफसरशाही अंदाज वाले डीजी के चेहरे के भाव शून्य ही रहे, यानी जैसे चल रहा है चलता रहेगा, और अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं है।

नि:संदेह ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस की तर्ज पर बनाई गई ईएसआई कार्पोरेशन बीमा आधारित होने के बावजूद विश्व की बेहतरीन चिकित्सा एवं सामाजिक सेवा है। पूर्णतया मज़दूरों के पैसे से चलने वाली यह सेवा किसी को मुनाफ़ा नहीं देती। मज़दूरों को सेवायें देने के बाद बचा पैसा कॉर्पोरेशन के कोष में ही जमा रहता है। मंत्रीजी ने कहने को तो बहुत बढ़िया बात कह दी परन्तु वास्तव में हो क्या रहा है? इतनी बेहतरीन सेवा देने वाला कार्पोरेशन आज चोर कंपनी बनकर कैसे रह गया? कोष में मज़दूरों से वसूले गये सवा लाख करोड़ से अधिक होने के बावजूद उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सेवायें क्यों नहीं मिल पा रहीं? मज़दूरों के इस पैसे को चिकित्सा सेवाओं में विस्तार की अपेक्षा अडानी के शेयर मार्केट में लगाने पर विचार कैसे किया जा सकता है? मरीजों की बढ़ती संख्या के अनुरूप स्टाफ़ की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही?

इसी शहर में मेडिकल कॉलेज के अलावा ईएसआई कार्पोरेशन का एक और अस्पताल तथा 14 डिस्पेंसरियां लगभग नाकारा हालत में हैं। डबल इंजन की सरकार चलाने वाले

मंत्रियों को यह सब नजर क्यों नहीं आता? उन्हें ये समझ क्यों नहीं आता कि उनके नाकारा होने से मेडिकल कॉलेज पर अत्यधिक कार्यभार बढ़ रहा है?

'मज़दूर मोर्चा' बीते कई वर्षों से लिखता आ रहा है कि कार्पोरेशन के मुख्यालय में बैठे अफसर निकम्मे व कामचोर होने के साथ-साथ प्राय: काम करने की समझ भी नहीं रखते। जो कभी डिस्पेंसरी स्तर के डॉक्टर कार्पोरेशन में भर्ती हुए थे, आज कार्पोरेशन के दस मेडिकल कॉलेजों के अलावा तमाम अन्य सेवाओं को भी देख रहे हैं जिसके लिये वे पूर्णतया अयोग्य हैं।

श्रम मंत्री से हमारा सीधा प्रश्न है कि कुछ वर्ष पहले तक दिल्ली के बसई दारापुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की भर्ती 110 प्रतिशत से भी ऊपर रहती थी आज 48 प्रतिशत कैसे रह गई? इसके लिये जिम्मेदार डॉक्टर दीपक शर्मा के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की जरूरत क्यों नहीं समझी गयी? कार्रवाई करना तो दूर, उन्हें मुख्यालय में बिठाकर तमाम मेडिकल कॉलेजों का बंटाधार करने का काम और सौंप दिया था। यह कहानी किसी एक मेडिकल कॉलेज की नहीं है, देश भर में कार्पोरेशन द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में 36 प्रतिशत से अधिक मरीज भर्ती नहीं हैं। यानी कि 64 प्रतिशत बेड खाली पड़े हैं। जाहिर है कि अपर्याप्त एवं घटिया सेवाओं के चलते मरीज़ वहां भर्ती होने से बचते हैं। कार्पोरेशन द्वारा राज्यों को सौंपे गये अस्पतालों की हालत तो इससे भी कहीं अधिक बुरी है।

पूर्व केन्द्रीय श्रम मंत्रियों ने अपने-अपने क्षेत्रों, मंडी, अलवर, गुलबर्गा तथा बिहटा में बीमाकृत मज़दूर न होते हुए भी बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर डाली थी। आज के केन्द्रीय श्रम मंत्री को गुड़गांव क्षेत्र में 2000 बेड वाले मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने में क्या समस्या है जबकि इस क्षेत्र में 20 लाख से अधिक बीमाकृत मज़दूर कार्पोरेशन को अंशदान देने को मजबूर हैं? अपने इस क्षेत्र में कुछ करने के नाम पर उन्होंने मात्र 500 बेड के एक अस्पताल का शिलान्यास किया है। इसके लिये साढ़े सात एकड़ का वह प्लॉट खट्टर सरकार से 120 करोड़ में खरीदा गया जिसका उनके पास कोई ग्राहक नहीं था। कोई पूछे यादव जी से कि खट्टर सरकार ने इतने महंगे भाव में कभी अपने अस्पतालों के लिये भी जमीन खरीदी है?

संदर्भवश **'मज़दूर मोर्चा'** अपने पाठकों को स्पष्ट कर देना चाहेगा कि यह निष्पक्ष न होकर उन मज़दूरों एवं तमाम मेहनतकशों का पक्षधर व मुखपत्र है जिनके साथ शासन व्यवस्था अन्याय करते हुए उनकी मेहनत की कमाई को लूट रही है। यह साप्ताहिक शासक वर्ग की चापलूसी एवं प्रशंसा करने के लिये नहीं बल्कि उन्हें कड़वी हकीकत से तीखे शब्दों में बयान करने के लिये चलाया जा रहा है। **'मज़दूर मोर्चा'** शासकों के प्रति केवल तभी सद्भावना रख पायेगा जब वे सद्भावना रखने वाले काम करेंगे।